तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धनराशि नियत करने का है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुथ्याल राव): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा 1968-69 में नियत की गई वित्तीय सहायता किसी अन्य राज्य को नियत की गई सहायता से अधिक है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

New Railway Lines in Maharashtra

2459. SHAI DEORAO PATIL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to construct new railway lines in the State of Maharashtra during the year 1969-70 and during the period of Fourth Five Year Plan ;

(b) whether Government propose to consider the construction of (i) Chanakha-Rajur (ii) Narkhed-Amraoti and (iii) Wardha-Kolhapur Railway lines in Maharashtra :

(c) if so, when these are likely to be started ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) The Fourth Five Year Plan proposals for new lines have not yet been finalised. Railway development is not based on any state-wise or region-wise concepts but on overall development considerations in the national interest. As such it is difficult to say which of the new lines that will be taken up in the 4th Plan will fall in Maharashtra.

(b) to (d). It is proposed to undertake surveys for a new line from Chanaka to Wani durtng 1969-70. A decision regarding the construction of this rail link will be taken after the surveys are completed and the results thereof known. Due to the present difficult ways and means position it is not possible to consider the construction of Narkhed-Amroati and Wardha-Kolhapur lines in the near future.

Tractor Factory in Maharashtra

2460. SHRI DEORAO PATIL : Will the Ministei of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government have demanded the establishment of a Tractor Factory in Public Sector in that State ;

(b) whether the request has been considered ; and

(c) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). Maharashtra was one of the several States which had asked the Central Government for the locatian of the proposed public sector project for the manufacture of tractors in that State. The State Government were informed that in view of a tractor manufacturing plant already located in Bombay, the location of another plant in that State would not be justified.

दिल्ली में अमृतसर एक्सप्रेस का देरी से पहुंचना

2461. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अमृतसर एक्सप्रेस दिल्ली में समय पर पहुंची थी ;

(ख) कितने मामलों में उक्त गाड़ी के देर से आने के कारण ठीक पाये गये थे ; और

(ग) जहां कारण सही नहीं पाये गये वहां उन मामलों में क्या कार्यवाही की गयी ; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि उक्त गाड़ी देर से न चले तथा भविष्य में समय पर आए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ;

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 57 डाउन बम्बई-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी 1968 में 70 बार समय पर नयी दिल्ली पहुंची ।

(ख) से (घ). इस गाड़ी के देर से चलने

के कई कारण हैं जिनमें अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचना, दूर-संचार उपस्करों की चोरी के कारण संचार व्यवस्था में खराबी और रास्ते के कुछ खण्डों में भीड़-भाड़ के कारण होने वाली परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां आदि शामिल हैं। अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने और दूर संचार के महत्वपूर्ण उपस्करों की चोरी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ उच्च-स्तरीय सम्पर्क रखा जाता है। जहां तक परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों का सम्बन्ध है, 1-3-1969 से इस गाड़ी के समय में कुछ समंजन किया जा रहा है ताकि इस गाड़ी के समय पालन में सुधार किया जा सके।

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

2462. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नई लाइनों के निर्माण के लिये 1969-70 के रेलवे आय-व्यय में कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या पश्चिमी नीमाड़ जिले में इस प्रयोजन के लिये कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ जिले में कोई नई लाइन बनाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1969-70 के बजट में गुना-मक्सी रेलवे लाइन के लिए 10 लाख रुपये की और सिंगरौली-कटनी रेल सम्पर्क के लिए 400 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और इन पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) से (घ). मध्य प्रदेश के पश्चिमी नीमाड़ और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में कोई नयी लाइन बनाने का या कोई सर्वेक्षण करने का विचार नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनें बनाने और आमान-परिवर्तन करने के लिए जो सीमित मात्रा में धन और साधन उपलब्ध होंगे, उन्हें प्रतिरक्षा के प्रयोजनों, बन्दरगाहों और मुख्य औद्योगिक विकास और भारी खनिज यातायात के परिवहन के लिए अपेक्षित आवश्यक आयोजनाओं के लिए सुरक्षित रखना होगा। इसलिए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नीमाड़ या छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में से किसी में भी कोई नई रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव को चौथी पंच वर्षीय योजना में अग्रता नहीं मिल पायेगी और इसके लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

Audit Cells for carrying out Inspection of Vehicles in Automobile Industry

2463. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to establish audit cells in each automobile factory to carry out the inspection and quality of each vehicle rolling out of the factory ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the date from which these cells have started working or will start working in each of the automobile factories in India ;

(d) whether the cost of running these audit cells will be passed on to the consumers in the shape of increased prices of vehicles : and

(e) if not, at whose cost these proposed audit cells will run ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The proposal for the establishment of a Technical Audit Cell for the Car Industry is under consideration. A team of Technical Experts appointed by Government is presently visiting the plants of the three car manufacturers with a view to assisting and advising the latter in strengthening their internal inspection organisation. The team will also suggest to Government the kind of external inspection